is not used in the thermal power plant industry.

(b) The coal supplied in India for power generation, has as ash content which varies from 35 to 49 per cent.

(c) Department of Coal is required to coordinate with Coal India Ltd. and to take appropriate steps to minimise the problem of the variation in the quality of coal from different coal mines. Coal supply contracts are being evolved to have a better control on coal quality in future.

(d) The land covered for ash disposal will depend upon the capacity of the power plant, ash context an the number of years of operation and varies from station to station.

(e) The Government is aware of the problem of land coverage which may result due to dumping of ash from thermal power stations. Appreciable amount of developmental work has been carried out to find variety of uses for the ash which includes reclaimation of waste land. as a constituent of cement, building and road matetrial, back filling of abandoned mines and as a fertilizer etc.

विद्युत उत्पादन के लिये प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग न किया जाना

2752. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विद्युत उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता का केवल 54 प्रतिशत ही इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप राज्यों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो पूरी प्रतिष्ठापित क्षमता का इस्तेमाल न किये जाने के क्या कारण है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू): (क) और (ख) अप्रैल, 1993 से फरवरी, 1994 को अवधि के दौरान, देश में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात, वर्ष 1990–91 के दौरान 54 प्रतिशत की तुलना में 68.2 प्रतिशत था । जल विद्युत और गैस केन्द्रों से विद्युत उत्पादन, जल, गैस और प्रणाली भार सम्बन्धी स्थितियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । देश में अधिष्ठापित क्षमता के ईष्टतम समुपयोजन के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, पुरानी यनिटों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने हेतु विद्युत बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करना, प्रचालन और रख-रखाव में कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त करना । जबकि ताप विद्युत संयंत्रों का क्षमता समुपयोजन बढ़ रहा है, तथापि कमी बनी हुई है क्योंकि निधियों मे कमी होने के कारण नयी उत्पादन क्षमता प्रतिबंधित की गयी है । जहां निधियों की कमी ने नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को प्रभावित किया है वहीं संयंत्रों के समयानुसार रखरखाव में को भी प्रभावित किया है ।

Revival package for the sick mills of NTC

2753. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what are the details of the proposed National Textile Corporation's revival package for its sick units;

(b) whether all the Trade Unions in the country have refused to accept the terms of the revival packags and are agitating on this issue; and

(c) if so, what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) The Cotton Textile Research Associations, have, on the directions of the Ministry of Textiles, prepared a fresh modernisation plan for the revival of NTC at a cost of Rs. 2005.67 crores The Sub Committee on the Special Committee on NTC, which includes representatives of INTUC, NLO, HMS, BMS, AITUC and CITU, have accepted the plan of the Cotton Textile Research Associations with the proviso that "restructuring with modernisation has to be done at each unit level. The report of the Sub Committee has been placed before the Special Committee on NTC

ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े का प्रावधान

2754. **श्री एस. एस. अहलवालिया** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों और महिलाओं को धोतियां, साड़ियां और कपड़े उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनायी है अथवा किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार कपड़े के उत्पादन और वितरण के लिए मिल क्षेत्र में कंट्रोल कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़ा योजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें समाज के कमजोर वर्ग, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के किसान और महिलाए भी शामिल हैं को उचित मूल्यों पर साड़ियां और धोतियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। सरकार कंट्रोल कपड़े और जनता कपड़े के उत्पादन पर सब्सिडी देती है।

आठवीं योजना के दौरान कपास का निर्यात

2755. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कपास के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कोई योजनाएं बनायी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनावधि में कपास के निर्यात के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्य क्या है; और

(ग) कपास के निर्यात में गुजरात का योगदान कितना होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) कपास निर्यात की मौजूदा नीति के अंतर्गत प्रत्येक कपास मौसम के प्रारम्भ में सरकार अपरिष्कृत कपास की 5 लाख गांठों को इस शर्त पर रिलीज करती है कि कपास के विस्तृत प्राक्कलन उपलब्ध होने के बाद उसे समायोजित कर दिया जाएगा। उसके बाद की रिलीज कीमत की स्थिति तथा घरेलू उपलब्धता का मूल्यांकन करने के बाद की जाती है। कपास के निर्यात के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के कपास मौसम के दौरान निर्यात के लिए रिलीज की गई 17.855 लाख गांठों और 5 लाख गांठों में से गुजरात राज्य सहकारी परिसंघ को क्रमश: 1.10 लाख गांठें और 0.40 लाख गांठें आवंटित की गई।